अशोका एक्सप्रेस

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती

संपादक :- विजय कुमार भारती

प्रबंधक :- सज्जन सिंह

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

Phone : 9810674206

● वर्ष: 26 ● अंक : 44 ● नई दिल्ली ● 01 से 08 दिसम्बर 2023 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती. द्रौपदी मुर्मू, महाराष्ट्र के खडकवासला में 75वें गौरवशाली वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए।

एमसीडी सदन में हंगामा : भाजपा पार्षदों ने दिखाई तख्तियां, कार्यवाही स्थगित; स्थायी समिति के गठन की मांग

नई दिल्ली दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। भाजपा पार्षद प्लेकार्ड लेकर स्थायी समिति या वार्ड समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। भाजपा ही नहीं कांग्रेस ने भी हंगामा किया। दिल्ली के सिविक सेंटर में दिल्ली नगर निगम के पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इसके बाद थोड़ी देर में ही भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के पार्षदों ने भी स्थायी समिति या वार्ड समिति के गठन की मांग की है।

इसके लिए 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं। जिन्हें सदन में से पास कराना है। सदन में पिछली बैठक हंगामे के चलते

महज पांच मिनट ही चल पाई थी और इस बीच 50 से यादा प्रस्ताव बिना चर्चा के पास किए गए थे। इस बार सदन की बैठक में निगम स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने और सफाई कर्मियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव हैं। डीबीसी कर्मियों के आश्रितों की भर्ती के संबंध में भी एजेंडा हैं, फिल्म पॉलिसी में परिवर्तन और एक जून को म्यूनिसिपल डे मनाने से संबंधित प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं। एजेंडे में शामिल एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया है कि ये निगम अधिकारियों द्वारा एजेंडे में शामिल किया गया प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को लेकर नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया।

उनका आरोप है आप पार्टी निगम के अफसरों से सांठ गांठ कर दिल्ली में टोल टैक्स एकत्रित करने वाली कंपनी को करीब 46 करोड़ रुपये का भुगतान कराने संबंधी प्रस्ताव पास कराना चाहती है। उन्होंने बताया कि इससे पहले ये प्रस्ताव निगम के पूर्व विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार के पास गया था, तब उन्होंने इस प्रस्ताव से संबंधित फाइल को कुछ आपत्तियां लगाकर वापस भेज दिया था। इसी प्रस्ताव को दोबारा सदन में लाकर पास कराने की तैयारी है। सदन में ये प्रस्ताव पास हुआ तो विपक्ष इसका जबरदस्त विरोध करेगा।

गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया

गरीबों को 5 साल और मिलता रहेगा मुफ्त राशन, महिलाओं को दी जाएगी ड्रोन की ट्रेनिंग

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी. इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा. ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया. 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है. वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है. कैबिनेट बैठक के दौरान जब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो भावुक हो गए. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर ले रहे थे. चुनाव प्रचार और कई कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे. पीएम मोदी ने टनल से बाहर निकले 41 श्रमिकों से फोन पर बातचीत की थी और मजदूरों की बहादुरी को लेकर तारीफ भी की. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी. सरकार ने इस योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक के बढ़ाने का फैसला किया है.

नेताओं की परख उनके साधारण कपड़ों से नहीं, उनकी संतानों को देखकर होती है : राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि कुछ नेताओं का मूल्यांकन उनके साधारण पहनावे या कम कीमत वाली घड़ियों के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि वे आम जनता से अपनी असली संपत्ति छिपाने में 'बहुत चतुर होते हैं। वह यहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के दिवंगत नेता पी सीथी हाजी पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के असली स्वभाव को उनके बचों को देखकर पहचाना जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''मैं कई नेताओं से मिलता हूं और जैसा कि आप जानते हैं, वे बहुत चतुर लोग हैं। आज के नेता आपको केवल वही दिखाएंगे जो वे आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, ''कभी-कभी जब वे मुझसे मिलने आते हैं, तो साधारण कपड़े, कम कीमत वाली घड़ियां और फटे जूते पहनकर आते हैं। जब आप उनके घर जाते हैं तो वहां उनके पास बड़ी बीएमडब्ल्यू होती हैं। ये लोग बहुत चतुर होते हैं। वे जानते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। उनके मुताबिक, नेता कपड़ों और पहनावे की अन्य चीजों के ज़रिये अपनी असलियत को छिपा सकते हैं, लेकिन ''जब बात उनके बचों की आती है तो सचाई को छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्हें इन व्यक्तियों का त्वरित और सटीक मूल्यांकन करने के लिए एक नए तरीके का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 18 साल बिताने और विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद लोगों के मूल्यांकन या परख का यह ''बुलेटप्रूफ तरीका इजाद किया है। गांधी ने कहा, ''मुझे यह बुलेटप्रूफ रास्ता ढूंढने में 18 साल लग गए, जहां किसी व्यक्ति के लिए अपने बारे में सचाई छिपाना असंभव होगा। मैं उनसे अपने बचों को मेरे पास भेजने के लिए कहता हूं। बचों के साथ, सचाई छिपाई नहीं जा सकती। हाजी आईयूएमएल के नेता और केरल की नौवीं विधानसभा में सत्तापक्ष के मुख्य सचेतक थे। राहुल गांधी के अनुसार, वह हाजी के बारे में यादा नहीं जानते क्योंकि वह उनसे कभी नहीं मिले, लेकिन उनके पुत्र पी.के. बशीर - को देखकर वह अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवंगत आईयूएमएल नेता किस तरह के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, ''मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह (बशीर) अपने पिता की छाप हैं। मैं उन्हें देखकर उनके पिता के बारे में जान सकता हूं। कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता।

मीठीबाई क्षितिज ने रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सिटी के सहयोग से 26/11 हमले में शहीद एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कैंडल मार्च का आयोजन

मुंबई, (अशोका एक्सप्रेस) 26/11 हमले के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित

करते हुए, टीम क्षितिज ने रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सिटी के साथ सहयोग किया और 26 नवंबर 2023 को एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो और मुंबई पुलिस के साथ गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कैंडल मार्च की मेजबानी की। टीम क्षितिज के सभी सदस्य इस शहर के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर नायकों की याद में सफेद कपड़े पहनकर कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए। मोमबत्तियाँ बाँटी गईं, और नारे वाले बोर्ड लगाए गए; उनके साहस के मौन मंत्रोच्चार ने सभी के दिलों को छू लिया। गेटवे ऑफ इंडिया पर हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि समीर वानखेड़े शामिल थे। मुंबई पुलिस, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई और ब्लैक कैट कमांडो के समीर वानखेड़े के साथ हमारी बातचीत ने हमें उनकी नौकरियों के सबसे अच्छे और सबसे बुरे हिस्सों के बारे में समझाया और बताया कि कैसे उनकी देशभक्ति किसी भी काम के

दौरान कमजोर नहीं होती है। इस उदास दिन की गूँज में, आइए हम आगे बढ़ने की प्रेरणा खोजें। साथ मिलकर, हम साहस, एकता और अटूट मानवीय भावना के लिए एक जीवित श्रद्धांजलि के रूप में खड़े हैं जो विपरीत परिस्थितियों की छाया से भी कम होने से इनकार करती है।, प्रिशा क्षितिज 23 के अध्यक्ष ठाकर ने कहा। समीर वानखेड़े ने जोर देकर कहा, प्रतिकूल परिस्थितियों में, हमारे शहर की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। 26/11 के शहीदों का बलिदान हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सिटी के अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने कहा, कठोर मौसम के बावजूद सम्मान देने के लिए इन छात्रों की उपस्थिति केवल शहीदों के प्रति उनकी देशभक्ति और सहानुभूति को उजागर करती है। मुझे उम्मीद है कि वे युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे और देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। क्षितिज टीम ने इन बहादुर आत्माओं की वीरता को याद किया, दिल गर्व से भर गया और क्षितिज जयकार और राष्ट्रगान के साथ मार्च को समाप्त कर दिया गया।

सम्पादकीय

निर्वाचन आयोग को दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति दी जाए

हाल ही में संपन्न तीखे मसालेदार चुनावी मौसम में हमारे नेतागणों ने अभद्र और तुच्छ भाषा का प्रयोग किया और एक तरह से बदबूदार मनोरंजन किया जिस पर कुछ लोगों ने ताली और सीटियां बजाई और यह सब कुछ इस आशा के साथ किया गया कि इससे उन्हें राजनीतिक तृप्ति मिलेगी। राज्य विधानसभा चुनाव 2023 में आपका स्वागत है जहां पर अनैतिकता और राजनीतिक बहस में गिरावट आम तौर पर देखने को मिली। देशभक्त से देशद्रोही, इन सबकी शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी ने की जिन्होंने कांग्रेस के राहुल को मूर्खों का सरदार कहा। इसका प्रत्युत्तर राहुल ने यह कहकर दिया कि पी.एम. मतलब पनौती मोदी और जेबकतरा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा गांधी परिवार भारत के राहू-केतु हैं। राहुल और प्रियंका की जड़ें इटली से जुड़ी हुई हैं। आप के केजरीवाल भी एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट किया जिसमें अडानी के पक्ष में मोदी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग का वर्णन किया गया और अडानी के साथ मोदी की फोटो लगाई जिस पर लिखा था कि मैं लोगों के लिए काम नहीं करता, मैं अपने मालिक के लिए काम करता हूं। इस पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा। ए.आई.एम.एम. के ओवैसी ने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक सके। मोदी आर.एस.एस. का पिट्ठू है, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। स्पष्ट कहूं तो इन सब बातों से मैं हैरान नहीं हूं क्योंकि हमारे नेतागण ऐसी भाषा का प्रयोग कर अपने गिरगिट के रंग को दिखा रहे हैं और उन्होंने सारी गरिमा और शालीनता को ताक पर रख दिया है। वे दिन लद गए जब कटाक्ष हास्यजनक और व्यंग्यात्मक होते थे और नेता उन्हें सहजता से लेते थे। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि विरोधी नेताओं के बीच अभद्र तू-तू, मैं-मैं देखने को मिलती है और जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे उतना आपको बेहतर माना जाता है। इस सबके लिए राजनीतिक दल दोषी हैं तथा निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए सबसे शक्तिशाली मिसाइल और जानी दुश्मन बन गई है। कोई भी आचरण, बैठकों, रैलियों, पोड्क्षलग बूथ, मतदान केंद्र पर्यवेक्षकों और सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में इस आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करता है। निर्वाचन आयोग से शिकायत तो तुरंत की जाती है किंतु विरोधियों के संबंध में स्वयं से किसी तरह के अनुशासन की अपेक्षा नहीं करते हैं। निर्वाचन आयोग चेतावनी देकर या 2-3 दिन के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है और घृणा भरे भाषणों के संबंध में निर्वाचन आयोग केवल फटकार ही लगा सकता है।

कॉप शिखर सम्मेलन 2023- जलवायु परिवर्तन पर प्राथमिकता से वैश्विक मंथन

वैश्विक स्तरपर दुनियां का हर देश जलवायु परिवर्तन के भीषण परिणाम से पीड़ित है, जिसका निदान करना और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना हर देश ही नहीं बल्कि हर मानवीय जीव का कर्तव्य है। पिछले दो दिनों वआज 29 नवंबर 2023 को हम देख रहे हैं ठंड का मौसम होने के बावजूद झमाझम बारिश हो रही है जो जलवायु परिवर्तन के दुष्टपरिणामो का ही असर है। पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए ही वैश्विक 28 वा कॉप वैश्विक शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक विचार विमर्श, मंथन कर सर्वसम्मति अनुमति से योजनाएं बनाकर वैश्विक स्तरपर क्रियान्वयन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें भारतीय पीएम भी शरीक होंगे। चूंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से आज पूरी मानव जाति पीड़ित है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, इसके खतरों से निपटने निर्धारित योजनाओं का सटीक क्रियान्वयन जरूरी है। साथियों बात अगर हम 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक चल रहे 28 वें कॉप शिखर सम्मेलन की करें तो, कॉप (सीओपी) का मतलब पार्टियों का सम्मेलन है। अभी तक इसकी कुल 27 बैठकें हो चुकीं हैं, बता दें कि पिछले कॉप 27 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्त्र के श्रम अल शेख में किया गया था । कॉप के तहत हर साल एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें दुनियां भर के राष्ट्राध्यक्ष ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए योजनाएं बनाते हैं इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में कारगर उपाय का आकलन करने और यूएनएफसीसीसी के दिशानिर्देश के तहत जलवायु परिवर्तन कार्रवाई करते हैं। बैठक का औपचारिक नाम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दलों का कॉन्फ्रेंस है। पहला कॉप 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। जलवायु कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए, वैश्विक उपभोग पैटर्न को सही करने की आह्वान किया गया है। बता दें 2021 में ग्लासगो में आयोजित जलवायु वार्ता में भीहमारे पीएम ने शिरकत की थी, जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की रणनीति तो उजागर किया था। पीएम ने पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को अपनाने के लिए जोर दिया था। मीडिया की मानें तो पीएम मोदी 30 नवंबर को यूएई जाएंगे और अगले दिन एक दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 30 नवंबर से दो दिसंबर को विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में तमाम देशों के नेता और प्रमुख संस्थानों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ रूप से लागू करने के लिए उद्देश्य से कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग मीथेन उत्सर्जन समेत विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए अमीर देशों की तरफ से विकासशील देशों को मुआवजे के तौर पर वित्तीय सहायता दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग, मीथेन उत्सर्जन, और ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन को कम करने समेत विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद है।जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए अमीर देशों की तरफ से विकासशील देशों को मुआवजे के तौर पर वित्तीय सहायता दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। साथियों बात अगर हम जलवायु परिवर्तन में कृषि क्षेत्र को देखें तो, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन किया जाना चाहिए ताकि कृषक समुदाय इससे लाभानवित हो सके।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसा अत्यधिक आबादी वाला देश शमन व लक्षित मीथेन कटौती की आड़ में खाद्य सुरक्षा परसमझौता नहीं कर सकता है। संयुक्त सचिव (एनआरएम) ने कार्बन क्रेडिट के महत्व को भी प्रस्तुत किया, जो जलवायु अनुकूल टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से कृषि में उत्पन्न किया जा सकता है। राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय बांस मिशन, प्राकृतिक/जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली आदि जैसे अनेक उपायों का आयोजन किया गया है। मिट्टी में कार्बन को अनुक्रमित करने की क्षमता है जिससे जीएचजी व ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कम हो जाता है।श्री तोमर ने सुझाव दिया कि कार्बन क्रेडिट का लाभ कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम के बीज फार्मों और आईसीएआर संस्थानों में मॉडल फार्मों की स्थापना के माध्यम से किसानों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवीके को कृषक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने में भी शामिल होना चाहिए, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सकें। कार्बन क्रेडिट, किसानों को सतत् कृषि का अभ्यास करने में प्रोत?साहन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्बन क्रेडिट के ज्ञान वाले किसानों को साथ लिया जा सकता है। साथियों बात अगर हम शिखर सम्मेलन के संबंध में ओईसीडी की रिपोर्ट की करें तो, हालांकि इस समिट से पहले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते सालों में हुए इन शिखर सम्मेलन में किए गये वादे पूरे नहीं हुए हैं, इसमें सबसे अहम वादा यह कि सभीविकसित देश पर्यावरण को बचाने के लिए सभी विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर देने का वादा किया था जोकि पूरा नहीं हुआ। विकसित देशों ने विकासशील देशों को देने के लिए सिर्फ 89.6 बिलियन डॉलर जुटाए। ओईसीडी इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्य रूप से यह अमेरिका, ब्रिटेन,जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा और अन्य समृद्ध देशों का एक समूह है। इस रिपोर्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दुबई में होने वाली इस बैठक का अहम विषय इस वादे को पूरा नहीं किए जाने को लेकर होगा। यह रिपोर्ट 2020 में ग्लासगो समिट के बारे में भी बताती है जहां पर इन विकसित देशों ने विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर दिए थे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी के दलों ने भी ग्लासगो में गहरे अफसोस के साथ कहा था कि विकसित देशों का समूह 2020 में तय समय में 100 अरब डॉलर के जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया था। ओईसीडी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनलों के माध्यम से जुटाए गए 73.1 बिलियन डॉलर में से 49.6 बिलियन डॉलर कर्ज के रूप में दिए गए थे।

हालांकि रिपोर्ट के आधार पर साझा की जाने वाली रिपोर्ट की मानें तो पर्यावरण की सारी चिंताएं जलवायु बचाए जाने के ऊपर निर्भर हैं। एक एनजीओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, दुनियां के सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोग 2015 में लगभग आधे वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। पिछले वर्ष अगस्त माह में भारत ने 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्र कार्य योजना को अपडेट किया। भारत के अद्यतन एनडीसी के लक्ष्य 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना, 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करना है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कॉप शिखर सम्मेलन 2023 - जलवायु परिवर्तन पर प्राथमिकता से वैश्विक मंथन।28 वां कॉप शिखर सम्मेलन दुबई 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 पर विशेष।जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है इसके खतरों से निपटने, निर्धारित योजनाओं का सटीक क्रियान्वयन ज़रूरी है।

यूपीः हलाल प्रमाणन प्रतिबंध, मंशा क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नंबवर 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि जो उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, उन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सरकार का कहना है कि ये उत्पादों के प्रमाणन की एक समांतार व्यवस्था है और भ्रम की स्थिति पैदा करती है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये निर्णय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और इस्लामोफोबिया से प्रेरित है? हलाल के बारे में ये गलत धारणा है कि ये सिर्फ मांस तक ही सीमित है। जबकि सच्चाई ये है कि मांस मात्र एक उत्पाद है, इसके दायरे में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे उत्पाद आते हैं। जैसे मेडिसन, कॉस्मैटिक्स, फूड ऑयल, शक्कर, कॉफी, बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी उत्पाद आदि। आसान शब्दों में, हलाल का अर्थ है जायज यानी इस्लाम में जिसकी अनुमति है और हराम का अर्थ है जिसकी अनुमति नहीं है। इसलिये ये सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद में इस तरह के किसी पदार्थ की मिलावट नहीं है जो हराम है और उसे बनाने की विधि भी जायज है, हलाल प्रामणन की आवश्यकता पड़ती है। यानी उत्पाद हलाल सर्टीफाइड है या नहीं, ये देखकर ग्राहक फैसला कर सकता है कि उसे इस उत्पाद का इस्तेमाल करना है या नहीं। उदाहरण के तौर पर सूअर के मांस और उत्पादों को इस्लाम में हराम माना गया है यानी उसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। जबकि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें बनाने में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार अगर उत्पाद हलाल सर्टिफाइड है तो एक तरह की गारंटी है कि इसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में सरकार खुद हलाल सर्टिफिकेशन का प्रबंध करती है। भारत में ये काम अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जो हलाल सर्टिफिकेशन के ग्लोबल स्टंडर्ड के मुताबिक काम करती है। ये संस्थाएं कंपनियों का निरीक्षण करती हैं, पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट की जांच करती है और स्टाफ की ट्रेनिंग का भी प्रबंध करती है। ये देखती है कि उत्पाद हाइजीनिक हो और नॉन-टॉक्सिक हो। ये संस्थाएं भारत सरकार के नियमों के हिसाब से काम करती हैं। 17 नवंबर, 2023 को शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति के द्वारा हलाल प्रमाणन जारी करने वाली तीन संस्थाओं के खिलाफ लखनऊ में एफआइआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में हलाल प्रमाणन जारी करने वाली संस्थाओं पर आरोप लगाया कि ये संस्थाएं मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, धार्मिक भावनाओं का दोहन कर रही हैं और आतंकी गतिविधियों को फंडिंग कर रही है। इसके अगले ही दिन पूरी सरकार हरकत में आ गई।

हलाल को यूपी की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया। हम जानते हैं कि कितने ही गंभीर मामलों में पुलिस एफ़आईआर तक दर्ज नहीं करती या कितने ही मामलों में पीड़ित थाने में मामला दर्ज तो कराते हैं लेकिन कार्रवाई होने में महीनों निकल जाते हैं, न्याय मिलना तो दूर की बात है। लेकिन इस मामले में यूपी सरकार ने एक दिन बाद ही त्वरित कार्रवाई शुरु कर दी। धड़ाधड़ छापेमारी होने लगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार बस एफ़आईआर का इंतजार ही कर रही थी या एफ़आईआर कराने की व्यवस्था कर रही थी। एक बात यह भी सोचने वाली है कि अगर हमारे देश में सरकारी तौर पर हलाल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है तो इसका उपाय यह नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को ही बैन कर दिया जाए, बल्कि इसके लिए नियम-क़ायदे बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि उपभोक्ता को ये पता होना चाहिए कि वो जिस उत्पाद को खरीदना चाहता है उस उत्पाद में क्या-क्या है और किस तरह बनाया गया है? आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे खाद्य पदार्थों के पैकेट पर हरे या लाल रंग की एक बिंदी बनी होती है। हरे रंग की बिंदी का अर्थ होता है कि उत्पाद शाकाहारी है और लाल रंग की बिंदी का अर्थ होता है कि उत्पाद मांसाहारी है। भारत में अलग-अलग फूड कल्चर और मान्यताओं के लोग रहते हैं, इसलिए उत्पाद के बारे में इस तरह की जानकारियां होना जरूरी है। ताकि आप फैसला कर पाएं कि आपको इस उत्पाद का इस्तेमाल करना है या नहीं? अन्यथा आपको धोखा हो सकता है, अगर गलती से शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी उत्पाद खाले, तो इसका मन पर सदमा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हर उत्पाद पर इस तरह की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां होनी चाहिए कि सभी धर्मों, मान्यताओं और फूड कल्चर के लोग पहले से ही उस उत्पाद के बारे में जान पाएं। इसे सिर्फ इस्लाम तक ही सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म या समुदाय के साथ ऐसी स्थिति हो सकती है। भारत विविधताओं से भरपूर देश है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग समुदायों की मान्यताओं में विरोधाभास हो। इसलिये उत्पादों के बारे में सभी जानकारियां पहले से ही होनी चाहिए और प्रमाणन की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला धार्मिक असहिष्णुता से प्रेरित तो है ही बल्कि व्यवसाय पर इसका खराब असर पड़ सकता है। अगर आप इसे सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित करके देख रहे हैं, तो आप गलत हैं। अडानी समूह, रिलायंस, टाटा से लेकर हिमालय आदि तक के उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि विदेशों में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की मांग काफी ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का प्रयोग करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी निर्यातित उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? जबकि मुस्लिम आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश पहले सात राज्यों में शुमार होता है।

मुस्लिम आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश छठे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश की 19% आबादी मुस्लिम है। यानी अब ये 19% आबादी जरूरत का सामन कहां से खरीदेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अधिकारी दुकानों और शॉपिंग माल पर छापे मारने लगे हैं और कार्रवाई करने लगे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मेनुफैक्चरर्स और व्यवसायी इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे? उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध एक गलत फैसला है। ऐसा लगता है कि योगी सरकार का ये फैसला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। ऐसा ही एक क़दम सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नाम पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर एक बार फिर उठाया गया है, जिसमें अभी तक की ख़बरों के मुताबिक सबसे ज़्यादा मस्जिदों को ही निशाना बनाया गया है। कुल मिलाकर एक बार फिर यूपी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है। समझा जा सकता है कि भाजपा चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल करेगी और राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश रहेगी।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें।

सुंदरलाल निभाएंगे अपना वादा, दयाबेन के आने का काउंटडाउन शुरू

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसायटी में इस वक्त खुशियों की लहर दौड़ गई है. भई...हो भी क्यों ना. सबकी प्यारी, सबकी चहेती दयाबेन जो वापस लौट रही हैं और अब तो खुद सुंदरलाल ने भी हरी झंडी दे दी है. जेठालाल ने सुंदरलाल से बात करने के लिए हर जुगाड़ लगा लिया और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सुंदरलाल को धमकी और चेतावनी से भरे मैसेज दिए. उनका उद्देश्य था कि जैसे भी सुंदरलाल से संपर्क हो जाए और उन्हें दया के वापस आने के बारे में कुछ पता चले. लेकिन मामला उल्टा पड़ गया क्योंकि वो सारे मैसेज अहमदाबाद पुलिस ऑफिसर की पत्नी को चले गए. लिहाजा जेठालाल को धमकी देने के आरोप में जेल तक की हवा खानी पड़ी. खैर जैसे तैसे वहां से वो बचकर आए तो गोकुलधाम आने पर सुंदरलाल से भी उनकी बात हो गई.अब सुंदरलाल ने जेठालाल को साफ साफ कर दिया है कि जो वादा उन्होंने किया था वो उसे जरूर पूरा करेंगे. और दिवाली पर उनकी बहना गोकुलधाम आकर घर में दीया जलाएगी. अब इस खबर को सुनकर जेठालाल, चंपक चाचा ही नहीं बल्कि सोसायटी का हर सदस्य खुशी से झूम उठा है. दर्शकों को भी उम्मीद बंध चुकी है कि वाकई इस बार तो जेठालाल की किस्मत वाकई चमकने वाली हैं और कई सालों के बाद ही सही दयाबेन वापस लौटने वाली है. शो में पहले भी कई बार दयाबेन की वापसी की बात कही गई लेकिन कभी भी वो नहीं आईं और हर बार दर्शकों को निराशा ही हाथ लगी. अब सवाल ये कि क्या इस बार पक्का दयाबेन शो में आ रही हैं या फिर इस बार भी कोई खेल हो जाएगा जो दर्शकों की फीलिंग्स पर भारी पड़ेगा.

सलमान खान की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सख्त, लॉरेंस बिश्नोई की ताजा धमकी के बाद उठाए गए कदम

सलमान खान अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं। काम के मोर्चे पर सलमान इन दिनों टाइगर 3 को लेकर हेडलाइंस का हिस्सा हैं। वहीं, निजी जिंदगी पर गौर फरमाए तो कुछ समय पहले, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि अभिनेता-गायक गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित आवास पर सलमान खान के साथ उनके करीबी संबंधों के कारण हमला किया गया था। अब, गैंगस्टर की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने खान की सुरक्षा की समीक्षा की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के यह कहने के बाद कि कनाडा में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमले का कारण सलमान खान संग उनकी निकटता थी ने भाईजान के फैंस की चिंता फिर से बढ़ा दी है। सलमान खान को वापस से धमकी जारी की गई है, इसलिए मंगलवार को मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा की समीक्षा की। अभिनेता को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। फिलहाल, टाइगर 3 अभिनेता के पास वाई प्लस सुरक्षा है। समीक्षा की पुष्टि करते हुए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, धमकी के बाद, अभिनेता की सुरक्षा की समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खामी न रहे।

हमने उनसे भी संपर्क किया है, और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा है, और उनकी सुरक्षा के संबंध में कुछ चीजों पर चर्चा की है। इससे पहले, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक फेसबुक अकाउंट ने कनाडा में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। पोस्ट में लिखा था, सलमान खान के साथ आपके करीबी रिश्ते आपकी रक्षा नहीं करेंगे। अब आपके भाई के लिए आगे आने और आपकी रक्षा करने का समय आ गया है। यह संदेश सलमान खान के लिए भी है - यह सोचकर मूर्ख मत बनो कि दाऊद इब्राहिम तुम्हें हमारी पहुंच से बचा सकता है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिद्धू मूस वाला की मृत्यु पर आपकी दिखावटी प्रतिक्रिया पर किसी का ध्यान नहीं गया। आप उसके चरित्र और उसके आपराधिक संबंधों से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने आगे कहा, जब तक विक्की मिद्दुखेड़ा जीवित थे तब तक आप हमेशा आसपास मंडराते रहे और बाद में आपने सिद्धू का अधिक शोक मनाया। आप भी अब हमारे रडार पर हैं, और अब आप देखेंगे कि धोखा देने का क्या मतलब होता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। किसी भी देश में भाग जाओ लेकिन याद रखो मौत के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती, वह वहीं आ जाएगी जहां उसे आना होगा। लॉरेंस बिश्नोई के संदेश के बाद, गिप्पी ग्रेवाल ने स्पष्ट किया कि उनका सलमान खान के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, सलमान खान से मेरी कोई दोस्ती नहीं है और इसका गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा है। मेरे लिए, यह अभी भी चौंकाने वाला है और मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है।

एनिमल की धुआंधार एडवांस बुकिंग जारी, बंपर ओपनिंग के लिए तैयार रणबीर कपूर की फिल्म

रणबीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना अभिनीत आगामी फिल्म एनिमल इस वर्ष की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। अर्जुन रेड्डी और उसके आधिकारिक हिंदी रीमेक कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके संदीप रेड्डी वांगा ने इस मूवी का निर्देशन किया है। फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है। एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद से ही सीटें तेजी से भर रही हैं। यूके और यूएस में फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग मामले में शानदार प्रदर्शन करती देखी जा चुकी है। वहीं, 25 नवंबर को भारत में शुरू हुई एडवांस बुकिंग मामले में फिल्म पांचवें दिन भी काबिल-ए-तारीफ प्रदर्शन करती देखी गई है। मूवी के अब तक का एडवांस बुकिंग कलेक्शन इसके ब्लॉकबस्टर होने का प्रमाण देता है। ताजा रिपोर्ट की मानें तो, एनिमल ने 29 नवंबर, 2023 की सुबह तक एडवांस बुकिंग में 13.95 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब तक फिल्म के 8,850 शोज के लिए 5,04,078 टिकटें बिक चुकी हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि एनिमल रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हो सकती है। एनिमल की एडवांस बुकिंग को देखते हुए इसके जरिए कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों और समीक्षकों के जरिए खूब सराहा गया है। विक्की कौशल की आगामी फिल्म सैम बहादुर से टकराव के बाद भी एनिमल का प्रदर्शन बेमिसाल है। रिपोर्ट तो ये भी हैं कि एनिमल, एडवांस बुकिंग मामले में सनी देओल की गदर 2 और शाहरुख खान की फिल्म जवान को भी टक्कर दे सकती है। जानकारी हो कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एनिमल की टिकट की कीमतें 250 रुपये से शुरू हैं। मल्टीप्लेक्स चेन में सामान्य सीटों के लिए टिकटें 600 रुपये तक में बिक रही हैं। रिक्लाइनर सीट के लिए 2400 रुपये तक की कीमत तय की गई है। मुंबई में भी टिकट की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। कुछ स्थानों पर यह 2200 रुपये तक पहुंच गई हैं। वहीं, इसकी एडवांस बुकिंग के मौजूदा रुझान को देखा जाए तो एनिमल, जवान को पछाड़कर तेलुगू रायों में हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। फिल्म में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, तृप्ति डिमरी, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एक दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

डीपफेक का नया शिकार बनीं आलिया भट्ट, बेडरूम में अश्लील हरकत करतें वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड अभिनेत्रियों रश्मिका मंदाना और कैटरीना कैफ के डीपफेक वीडियो के कुछ हफ्तों बाद देश में हलचल मच गई, अब ऐसा लगता है कि बी-टाउन की एक और प्रमुख अभिनेत्री नवीनतम शिकार है। प्रशंसित अभिनेत्री आलिया भट्ट अपने एक डीपफेक वीडियो के इंटरनेट पर आने के बाद फिर से खबरों में हैं। कथित वीडियो में भट्ट के चेहरे को कम कपड़े पहने एक महिला के चेहरे में बदल दिया गया है, जो कैमरे की ओर देखते हुए तरह-तरह के इशारे करती नजर आ रही है। डीपफेक की समस्या वास्तविक है क्योंकि अगर इसे अनियंत्रित किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालाँकि उनमें अंतर पहचानना हर किसी के लिए आसान प्रतीत होता है, लेकिन ऐसे वीडियो व्यक्तियों और व्यवसायों की प्रतिष्ठा और सद्भावना पर कहर बरपा सकते हैं। भले ही बताने योग्य संकेत हों, लाखों ऐसे इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर बताने में असमर्थ होंगे। डीपफेक का मुद्दा एक बार फिर लाखों सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सामने ले आया है। ऐसे AI–हेरफेर किए गए वीडियो के सामने आने के बाद से, उन सभी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है जो शॉर्ट-फॉर्म वीडियो सामग्री साझा करते हैं। यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं जो किसी को अपने वीडियो और छवियों को डीपफेक बनाने वाले शरारती तत्वों के जाल में फंसने से बचाने में मदद कर सकती हैं। वीडियो में आलिया का चेहरा एक अलग महिला का रूप दिया गया है। वीडियो में महिला को कैमरे की ओर देखते हुए और अश्लील इशारे करते हुए दिखाया गया है। कुछ दिनों पहले काजोल का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वास्तव में एक ब्रिटिश सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्ति का था, जिसने तथ्य-जांच प्लेटफार्मों के अनुसार, गेट रेडी विद मी ट्रेंड के हिस्से के रूप में इस क्लिप को टिकटॉक पर साझा किया था। पीएम मोदी ने एआई, विशेष रूप से डीपफेक द्वारा उत्पन्न खतरों पर भी चिंता व्यक्त की है, उन्होंने कहा, हमें लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, यह कैसे काम करता है, यह क्या कर सकता है, यह क्या चुनौतियां ला सकता है और जो कुछ भी हो सकता है इससे बना है। इससे पहले रश्मिका ने अपने डीपफेक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, ईमानदारी से कहूं तो यह बेहद डरावना है, न केवल मेरे लिए, बल्कि हममें से हर एक के लिए जो आज प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण बहुत अधिक नुकसान की चपेट में है।

बॉबी की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है एनिमल :28 साल में सिर्फ 6 फिल्में हिट, बुरे दौर में सलमान से कहा- मामू मुझे काम दे

फिल्म 'एनिमल' 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें बॉबी देओल विलेन बने नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिल्म में बॉबी का कैरेक्टर बहुत ही यूनीक है। 'एनिमल' में उनका एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो सरप्राइज पैकेज से कम नहीं होंगे। वैसे, एनिमल करियर के लिहाज से बॉबी के लिए बेहद अहम् फिल्म है। वो बॉलीवुड में 28 साल से हैं, लेकिन आज तक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए तरस रहे हैं। उनकी 40 में से 28 फिल्में डिजास्टर साबित हुई हैं और केवल 6 फिल्में हिट हुई हैं। बुरे दौर में उन्होंने सलमान खान से मदद मांगते हुए कहा था, मामू मुझे काम दे। उम्मीद की जा रही है कि एनिमल के जरिए बॉबी के करियर से ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सूखा मिट जाएगा और उन्हें जबरदस्त सफलता मिलेगी।

बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धरम-वीर से की थी। 1977 में आई इस फिल्म में बॉबी के पिता धर्मेंद्र ने लीड किरदार निभाया था। उस दौरान बॉबी महज 8 साल के थे।

1995 में 'बरसात' से किया डेब्यू

बतौर हीरो बॉबी ने 1995 में रिलीज हुई फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। इस फिल्म से ट्विंकल खन्ना ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म को रिलीज होने में काफी मुश्किलें आई थीं। एक इंटरव्यू में बॉबी ने बताया था कि इसे बनने में पूरे पांच साल लग गए थे; क्योंकि पहले शेखर कपूर फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन 27 दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने फिल्म 'बैंडिट क्वीन' के लिए फिल्म 'बरसात' को छोड़ दिया था। इसके बाद फिल्ममेकर

राजकुमार संतोषी फिल्म से जुड़े लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा, जिससे इसकी मेकिंग और डिले हो गई। फिल्म बरसात जब बननी शुरू हुई तो बॉबी 22 साल के थे और रिलीज के वक्त वो 26 साल के हो चुके थे। फिल्म सुपरहिट रही। बादल का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म से बॉबी को देशभर में पहचान मिली और फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड भी मिला।

जब बरसात ने तोड़ा डीडीएलजी का रिकॉर्ड

बरसात 10 करोड़ में बनी थी। इसकी टोटल कमाई 19.56 करोड़ थी। फिल्म ने 1995 में आई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की ओपनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। बरसात का ओपनिंग डे कलेक्शन 68 लाख रूपए और वीकेंड कलेक्शन 1.96 करोड़ रुपए था। वहीं, डीडीएलजी ने पहले दिन 55 लाख और पहले वीकेंड पर 1.56 करोड़ का बिजनेस किया था।

3 हिट देने के बाद पिटने लगीं फिल्में

फिल्म बरसात के बाद बॉबी ने अपने करियर में 3 फिल्में गुप्त (1997), सोल्जर (1998) और बादल (2000) जैसी हिट दी थीं। इसके बावजूद बॉबी को खास फिल्में नहीं मिलीं। उन्होंने कुछ फिल्में कीं जैसे किस्मत, बर्दाश्त, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, झूम बराबर झूम, नन्हे जैसलमेर, पोस्टर ब्वायज लेकिन ये सब पिट गईं। उन्हें छोटे-मोटे साइड रोल मिलने लगे। 2011 में उन्होंने फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया था, लेकिन इस मल्टीस्टारर फिल्म से बॉबी के करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिला।

काम न मिलने पर नशे में डूबे बॉबी

एक समय ऐसा आया जब बॉबी को फिल्मों के अछे ऑफर मिलने बंद हो गए। एक ओर पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम है। वहीं, बॉबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझने लगे। इस बात से वो परेशान रहने लगे और नशे में डूबने लगे। बॉबी ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैं इतनी शराब पीने लगा था कि मुझे खुद पर तरस आने लगा था। मैं सोचता था कि आखिर मुझमें क्या कमी है जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते।

नई दिल्ली (इंद्रजीत सिंह)महावीर इन्टरनेशनल दिल्ली द्वारा आयोजित नेत्र दिवस पर संस्था के चिकित्सक निदेशक बिग्रेडीयर आर एस भाटिया व सचिव श्री अरूण जैन से श्री राजेन्द्र खर्रा को सामाजिक कार्य के उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया. छाया-अशोका एक्सप्रेस

कई शीर्ष न्यायाधीश कानूनी सहायता अधिकार जल्द शुरू होने पर सहमतः सीजेआई चंद्रचूड़

नई दिल्ली।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि कई देशों के शीर्ष न्यायाधीश इस बात पर सहमत हैं कि कानूनी सहायता का अधिकार 'जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसी आरोपी की गिरफ्तारी से पहले ही शुरू कर दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों को न केवल विद्यार्थियों, बल्कि जनता को भी इस बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश यहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की ओर से कानूनी सहायता तक पहुंच- ग्लोबल साउथ में न्याय तक पहुंच को सशक्त बनाना विषय पर आयोजित दो-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित थे। सम्मेलन में उनके अलावा, बांग्लादेश, कैमरून, इक्वेटोरियल

गिनी, इस्वातिनी, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, नेपाल, जिम्बाब्वे के प्रधान न्यायाधीश और कजाकिस्तान, नेपाल, पलाऊ, सेशेल्स, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, तंजानिया और जाम्बिया के न्याय मंत्रियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, सभी प्रधान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कानूनी सहायता का अधिकार प्रारंभिक चरण से शुरू होना चाहिए, यहां तक कि गिरफ्तारी से पहले ही। उन्होंने कहा, हमने स्वीकार किया है कि न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह कानूनी सहायता प्रक्रिया का एक आंतरिक तत्व है। इस अवसर पर, उचतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा कि कानूनी सहायता प्रदान करने और जरूरतमंद नागरिकों तक न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग अगले कुछ दशकों में निर्णायक कारक होगा। न्यायमूर्ति कौल ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक 'उल्लेखनीय योगदान कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल कोर्ट या ई-कोर्ट के रूप में सामने आया। न्यायमूर्ति कौल नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि अनुमानत दुनिया की कुल आबादी के दो-तिहाई हिस्से के पास न्याय तक प्रभावी पहुंच का अभाव है, और ग्लोबल साउथ (अल्पविकसित देश) में वंचितों की बहुतायत है।

उन्होंने कहा कि ऐसे में वहां न्याय तक पहुंच एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में एक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था, जहां कानून का शासन सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधि और साझा आर्थिक विकास का एक आवश्यक आधार है। उन्होंने कहा कि कमजोर आबादी के लिए विशेष मंचों और योजनाओं की आवश्यकता है ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने अधिकारों का दावा कर सकें।

नेपाली दूतावास के संस्कृति और शिक्षा विभाग के प्रमुख येदुनाथ पौडेल का विदाई समारोह

नई दिल्ली (इंद्रजीत सिंह)प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (दिल्ली) में यूनाइटेड की ऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली की पहल पर, दिल्ली में नेपाली दूतावास के संस्कृति और शिक्षा विभाग के प्रमुख येदुनाथ पौडेल, जो पूरा होने के बाद घर लौटने वाले हैं उनका दो वर्ष से अधिक का सफल कार्यकाल रहा द्य उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया।

जो अपने सफल कार्यकाल के दौरान वे नेपालवासियों की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने हेतु आम समुदाय तक पहुँचने का माध्यम बने। विदाई समारोह का संचालन सोसायटी के सचिव बिष्णु केसी ने किया. अध्यक्षता सोसायटी के अध्यक्ष बी. के. कृष्णा ने की द्य सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य और संस्थापक शेखर कुवर विशिष्ट अतिथि थे देवेन्द्र कुवंर ने कहा कि येदुनाथ पौडेल 2 वर्षों से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे प्रवास के दौरान प्राप्त अनेक उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त किए द्य हमारा समाज उन्हें भारतीय दूतावास से विदाई देता है और भविष्य में उनकी और सफलता की कामना करता है। इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य एवं

राष्ट्र टाइम्स के सम्पादक विजय शंकर चतुर्वेदी का भी उपस्थिति सदस्यों ने गर्म जोशी से स्वागत किया. विदाई समारोह में शिव के. सी. लाली, संदीप भट्ट, राजू पेरियार, कृष्णा शर्मा, मॉडल प्रकाश शर्मा, सुपेदुराली से जेबी थापा उपस्थित रहे.

मंगलुरु ब्लास्ट केस में एनआईए ने दो आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, आईएस से जुड़े होने का दावा

नई दिल्ली । कर्नाटक के मंगलुरु में पिछले साल नवंबर में हुए इस्लामिक स्टेट (आईएस) प्रायोजित प्रेशर कुकर विस्फोट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दो आरोपियों के खिलाफ बुधवार (29 नवंबर) को चार्जशीट फाइल की है. आरोपियों में से एक, मोहम्मद शारिक जोकी 19 नवंबर 2022 को एक ऑटो-रिक्शा में प्रेशर कुकर आईईडी ले जा रहा था उस समय में उसमें अचानक विस्फोट हो गया था. एनआईए का कहना है की आरोपी ने हिंदू समुदाय के बीच आतंक फैलाने के मकसद से मंगलुरु के कादरी मंजुनाथ मंदिर में आईईडी लगाने की योजना बनाई थी लेकिन कम तीव्रता वाला बम गलती से रास्ते में फट गया था. इसको लेकर 23 नवंबर 2022 को आईपीसी की धारा 120बी और 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला (आरसी-47/2022/एनआईए/डीएलआई) दर्ज किया गया था. एनआईए ने शारिक को उसके सह-अभियुक्त साथी सैयद शारिक के साथ जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था.

एनआईए ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है. एनआईए की जांच के अनुसार, शारिक और सैयद ने एक ऑनलाइन हैंडलर के साथ मिलकर खिलाफत (शरिया कानून) स्थापित करने की साजिश के तहत विस्फोट की योजना बनाई थी. साजिश के तहत, मोहम्मद शारिक ने प्रेशर कुकर आईईडी तैयार किया था और सैयद यासीन ने विस्फोटक के लिए सामग्री सहायता प्रदान की थी.

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिलेगा सेवा विस्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार को मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिए गए 6 महीने के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है. दिल्ली की आप सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था. बता दें, नरेश कुमार गुरुवार (30 नवंबर 2023) को रिटायर होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है.

मैं कुछ कह रहा था और वह कुछ और..., राहुल गांधी ने भाषण के अनुवाद पर साझा किया दिलचस्प किस्सा

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक दिलचस्प किस्सा साझा किया कि कैसे तेलंगाना में उनके एक भाषण के अनुवादक को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांधी ने यह किस्सा एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बयां किया, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सांसद अब्दुस्समद समदानी उनके भाषण का अनुवाद करने के लिए मौजूद थे। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने मजाक में कहा कि उनका अनुवादक बनना एक खतरनाक काम हो सकता है। तेलंगाना में एक चुनावी रैली में अपने हालिया भाषण का उदाहरण देते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा कि अनुवादक ''बहुत परेशानी में पड़ गये। राहुल गांधी ने कहा, ''मैं कुछ कह रहा था और वह (अनुवादक) कुछ और कह रहे थे। फिर, कुछ समय बाद मैंने अपने शब्द गिनने शुरू कर दिए... वह तेलुगु में बोल रहे थे। इसलिए, मैंने सोचा कि अगर मैं हिंदी में पांच शब्द बोलूं, तो इसका तेलुगु में अनुवाद करने में पांच या सात शब्द लगेंगे, लेकिन वह 20, 25, 30 शब्द बोलते थे। उन्होंने कहा, ''कभी-कभी मैं कुछ बहुत उबाऊ बात भी कह देता था तो भीड़ बहुत उत्साहित हो जाती थी।

मां का बयान नजरअंदाज, 13 साल की किशोरी की बात मान हाईकोर्ट ने दुष्कर्मी की सजा रखी बरकरार

चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी की सजा के खिलाफ अपील को पीड़िता के बयान को आधार बनाते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पीड़िता की मां के बयान को नजरअंदाज करते हुए पीड़िता के बयान में विश्वास दिखाया और याची की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। याचिका दाखिल करते हुए दोषी ने सोनीपत जिला अदालत द्वारा दोषी करार देने और उम्रकैद की सजा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची ने कहा कि इस मामले में पीड़िता की मां का बयान पीड़िता से बिलकुल अलग और विपरीत है। ऐसे में पीड़िता के बयान की अहमियत नहीं रह जाती और वह विश्वास खो देती है। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में भी याची को सीधे तौर पर दोषी नहीं करार दिया गया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने सजा के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा कि हम पीड़िता की गवाही पर विश्वास करते हैं। याची के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं यह सब पीड़िता की बेदाग गवाही पर निर्भर है, न कि उसके विपरीत दी गई मां की गवाही पर। जब पीड़िता ने खुद गवाही देकर पूरी घटना का विवरण दे दिया है तो उसकी मां की उसके खिलाफ दी गई गवाही महत्वहीन हो जाती है। एफआईआर के अनुसार 13 वर्षीय किशोरी ने बीमार पड़ने और उल्टी शुरू करने के बाद अपने माता-पिता को घटना के बारे में सूचित किया था। जांच की गई और सामने आया कि पीड़िता सात सप्ताह की गर्भवती थी। चिकित्सा साक्ष्य की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। याची पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने दलील दी कि उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि पीड़िता और उसकी मां ने विरोधाभासी बयान दिए थे। ऐसे में पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता खत्म हो गई। हाईकोर्ट ने डॉक्टर की गवाही पर भी गौर किया, जिसने पीड़िता की जांच की थी और कहा था कि उसे सात सप्ताह के जीवित भ्रूण के साथ भर्ती कराया गया था। इसका विरोध करते हुए याची ने कहा था कि डीएनए रिपोर्ट अनिर्णायक थी और ऐसे में उसे दोषमुक्त करार दिया जाए। हाईकोर्ट ने याची की सभी दलीलों को रद्द करते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया।

इंस्पेक्टर से डीएसपी पदोन्नति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने विभागीय पदोन्नति समिति को दी अनुमति

चंडीगढ़ । हरियाणा में इंस्पेक्टर से डीएसपी की पदोन्नति का रास्ता साफ करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को (विभागीय पदोन्नति समिति) डीपीसी की बैठक करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले इस्पेक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस बैठक पर रोक लगा दी थी। याचिका दाखिल करते हुए इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह व अन्य ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इंस्पेक्टर से डीएसपी की पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ की है। याचिकाकर्ताओं को जानकारी मिली कि इस प्रक्रिया में आरक्षण को लागू किया गया है।

याची ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इंस्पेक्टर के रूप में आवश्यक वर्षों की सेवा उन्होंने पूरी कर ली है और डीएसपी पद पर पदोन्नत होने के पात्र हैं। 27 सितंबर को डीजीपी ने डीएसपी के पद पर पदोन्नति के लिए इंस्पेक्टरों के आवेदन मांगे थे और इसमें याचिकाकर्ताओं के नाम का भी उल्लेख था। याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के आदेश पारित होने से पहले, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के माध्यम से 25 अक्टूबर को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी किए। उसके बाद 25 अक्टूबर को सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति से संबंधित इंस्पेक्टरों के मामले को डीएसपी के पद पर पदोन्नति के लिए बुलाया गया जो याचिकाकर्ताओं से जूनियर हैं। याची ने कहा कि इस प्रकार आरक्षण लागू करना शीर्ष अदालत द्वारा पारित फैसले का उल्लंघन हैं। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने 16 मार्च 2006 को इस तरह के निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को त्वरित वरिष्ठता प्रदान की थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने प्रेम कुमार वर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में सरकार के निर्देशों को रद्द कर दिया था।

हरियाणा में कोहरे की दस्तक : सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, बूंदाबांदी के बाद मौसम में आया बदलाव

सोनीपत (हरियाणा) । सोनीपत में दो दिन हुई बूंदाबांदी के बाद देर रात बादल छटे तो बुधवार सुबह मौसम का पहला कोहरा छा गया। कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्रामीण क्षेत्र में काफी देर रात कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग गई है। बुधवार सुबह लोग सोकर उठे तो घना कोहरा छाया था। इस सीजन के पहले कोहरे से वाहनों की गति को रोक दिया। दो दिन तक हुई बूंदाबांदी के चलते पहले ही मौसम विशेषज्ञ ने बादल छटते ही कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की थी। मंगलवार रात को ही बादल छट गए थे। जिसके चलते बुधवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे अचानक कोहरा छा गया। इससे दृश्यता कम हो गई। सुबह महज 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। वहां 20 मीटर तक ही दृश्यता रह गई थी। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को झेलनी पड़ी। वाहनों को धीमी गति से चलाना पड़ा। शहरी क्षेत्र में सुबह आठ बजे और ग्रामीण क्षेत्र में 10 बजे के बाद हल्की धूप खिली, जिसके बाद दृश्यता में सुधार हो सका।

परिवार की 3 पीढ़ियों ने पीया लाडली भैंस का दूध... मरने पर किया मृत्युभोज

चरखी दादरी ।

किसान परिवार की तीन पीढियों को करीब 24 वर्ष तक मालामाल करने वाली भैंस के निधन पर जहां विधि विधान से क्रिया कर्म किया। वहीं उसकी मौत के बाद न केवल अस्थियां विसर्जित की बल्कि सत्रहवीं की भी रस्में निभाई। भैंस को लाडली के नाम से पुकारने वाला किसान परिवार द्वारा मृत्युभोज का आयोजन किया गया। इसके लिए बकायदा नाते-रिश्तेदारों के अलावा ग्रामीणों को आमंत्रण भी भेजा गया और लोगों को देशी घी का लजीज खाना भी परोसा गया। किसान परिवार के अपने पालतू पशु के प्रति प्रेम की चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि गांव चरखी निवासी किसान सुखबीर सिंह के पिता रिसाल सिंह करीब 28 साल पहले एक भैंस लेकर आए थे। जिससे पैदा हुई कटिया का पालन-पोषण किया और

किसान के घर भैंस ने लगातार 24 बार कटिया को जन्म देकर रिकार्ड बनाया। ÷लाडली÷ भैंस का परिवार की तीन पीढ़ियों ने दूध पिया और उससे जन्म लेने वाले बच्चों को तैयार करते हुए काफी पैसा भी कमाया। पिछले दिनों अपनी पालतू भैंस का निधन पर होने पर परिवार ने पूरा शोक मनाते हुए विधि विधान से सभी क्रिया क्रम करते हुए अस्थियां भी विसर्जित की। भैंस की सत्रहवीं पर किसान परिवार ने अपने घर पर मृत्युभोज का आयोजन किया। इसके लिए बकायदा लोगों को आमंत्रण भी भेजा गया। मृत्युभोज के दौरान नाते-रिश्तेदारों को देशी घी का लजीज भोजन भी परोसा गया। पालतू पशु के निधन पर मृत्युभोज कार्यक्रम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान सुखबीर सिंह ने बताया कि वे अपनी भैंस को लाडली के नाम से पुकारते थे और परिवार का सदस्य मानते थे। उनके तीन पीढ़ियों ने भैंस का दूध पिया है।

भैंस ने अपने पूरे जीवन में लगातार 24 बार कटिया को ही जन्म देते हुए रिकार्ड बनाया है। अपनी भैंस से इतना प्यार था कि उसने उसकी मौत के बाद सभी क्रिया-क्रम करते हुए मृत्युभोज का आयोजन करवाया। किसान सुखबीर ने बताया कि भैंस के मृत्युभोज कार्यक्रम में देशी घी का खाना तैयार किया गया। जिसमें चावल, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, सब्जी व पूरी शामिल रही। वहीं शादी की तरह गोल-गप्पे भी परोसे गए। किसान के अनुसार करीब चार सौ नाते-रिश्तेदार भैंस के मृत्युभोज कार्यक्रम शामिल हुए।

शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील सरकार, खुलेंगे प्रदेश में 4 हजार प्ले स्कूल

चंडीगढ़ ।

तमाम विपक्ष का मुंह बंद करते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश में जो प्रबंध किए हैं उसकी लोगों में तरीफ हो रही है। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरतें शिक्षा और स्वास्थ्य ही होती हैं, जिन पर सबसे अधिक पैसा जनता का खर्च होता है। हरियाणा में मनोहर सरकार के सत्तासीन होने के बाद इन्हीं पर अधिकांश फोकस किया गया है। हरियाणा सरकार ने जहां हर जिले में स्कूल-कॉलेज खोलने पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं विश्वविद्यालयों का वित्त प्रबंधन और अधिक पोषित किया है। जिससे शिक्षा की तरफ लोगों का विशेष ध्यानाकर्षण हुआ है और लोग सरकार की शिक्षा नीति की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान और चिरायु जैसी योजनाएं देकर लोगों की बड़ी चिंता दूर की है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश के विपक्षी दलों के नेता सरकार के कामकाज पर उंगली उठा रहे थे। हाल ही में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक झटके में ही 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान करके विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। मनोहर सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत में क्रांति की शुरूआत हुई है। इसके बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों से शिक्षकों की कमी तो पूरी होगी ही, इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। मुख्यमंत्री की हर जिले में मेडीकल कॉलेज खोलने की योजना भी मूर्त रूप ले रही है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, वहां या तो घोषणाएं हो चुकी हैं या फिर उन पर काम भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर चलते हुए बिना किसी क्षेत्रवाद के काम कर रहे हैं और उनकी हर नीति से पूरा सूबा प्रभावित और लाभान्वित होता है। अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समर्पण के तहत ही मुख्यमंत्री ने कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज वाले मरीजों को पेंशन देने की योजना लांच करके लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मजे की बात यह है कि कैंसर के पीड़ित लोग पहले से पेंशनभोगी हैं, उन्हें भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। अभी हरियाणा में चुनाव दूर हैं लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से घोषणाओं का अंबार लगाया है और पुरानी घोषणाएं जल्द पूरी करने की दिशा में काम किया है। उसका लाभ सरकार को मिलना अवश्यंभावी है।

ढोली की जमीन का मालिकाना हक ब्राह्मण समाज को देना बेहतरीन कदम : कार्तिकेय शर्मा

चंडीगढ़ । राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मुहिम आखिरकार रंग लाई.. सरकार ने ढोली की जमीन का मालिकाना हक ब्राह्मण समाज को दे दिया है... इसके बाद अब ब्राह्मण ढोली में मिली जमीन भी बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में धौली की करीब 1700 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की घोषणा की थी। वर्षों पहले दान में दी गई धौली की जमीन का मालिकाना हक और उसे बेचने का अधिकार ब्राह्मण समाज को मिल गया है। इस संदर्भ में वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा उठाई गई मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में धौली की

करीब 1700 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा की थी हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को आदेश दिया है कि हरियाणा धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकररिदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत किसी निजी व्यक्ति/संस्था की जमीन को धौलीदारों आदि में निहित कर दिया गया है. दान में दी गयी जमीन को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. पत्र में सभी उपायुक्तों से जिले के सभी निबंधन पदाधिकारियों को भी जागरूक करने को कहा गया है. संबंधित धौलीदारों द्वारा उनके पक्ष में उत्परिवर्तन की मंजूरी के बाद बिक्री कार्यों आदि के आगे पंजीकरण के लिए जागरूक किया जाएगा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मांग को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त किया है, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित महाकुंभ में ब्राह्मण समाज की सभी मांगों को पूरा किया है. सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सांसद बनने के बाद ब्राह्मण समाज के लोग लगातार यह मांग उनके सामने रख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस मांग को सरकार और सीएम तक पहुंचाने का काम किया और आखिरकार करनाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में सीएम ने इस मांग पर अपनी मुहर लगा दी. उन्होंने अपना कार्य किया जिसके लिए पूरा समाज उनका आभारी है।

बीसीसीआई ने बायजूज के खिलाफ बायजूस में इन्सॉल्वेंसी याचिका दायर की

नई दिल्ली ।

देश की दिग्गज एडटेक कंपनी बायजूस एक बार फिर मुश्किलों में आ गई है। नया मामला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़ा है। बीसीसीआई ने बायजूज के खिलाफ NCLT में इन्सॉल्वेंसी याचिका दायर की है। बीसीसीआई ने ये मामला NCLT बेंगलुरु में 8 सितंबर को दायर किया है। NCLT वेबसाइट के मुताबिक, 8 सितंबर को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत बीसीसीआई ने याचिका दायर की थी। इस मामले में बायजूस के एक प्रवक्ता का कहना है कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए बीसीसीआई के साथ चर्चा कर रहे हैं और कंपनी को उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही सुलझा लेंगे। बता दें, बायजूस 2019 से इस साल जनवरी तक सभी भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जर्सी का मेन स्पॉन्सर रहा है। इस साल बायजूस ने बीच में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का फैसला किया था। इस अवधि तक के सभी भुगतान बायजू द्वारा किए गए थे। इस समय, बीसीसीआई ने उस कंपनी को, जो कभी सबसे मूल्यवान स्टार्टअप थी, तब तक जारी रखने के लिए कहा था जब तक उसे नया प्रायोजक नहीं मिल जाता। फंडिंग सर्दी के बीच, बायजू बाहर निकलना चाहता था लेकिन बीसीसीआई ने उसे कुछ और समय के लिए रुकने के लिए मना लिया। एक एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि जून में, बायजूस ने बोर्ड के साथ अपने जर्सी प्रायोजन समझौते को अनुमानित 35 मिलियन में नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। जहां बायजूस दिसंबर से बीसीसीआई के साथ अपना समझौता खत्म करना चाहता था, वहीं बोर्ड चाहता था कि इसे कम से कम मार्च 2023 तक जारी रखा जाए ताकि नए वित्तीय वर्ष से नया प्रायोजक आ सके। सूत्रों ने बताया कि यह विवाद इस अवधि के लिए 160 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ा है। दिवाला विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों के बकाया भुगतान के साथ, बीसीसीआई के बकाया को कम प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि यह एक परिचालन ऋणदाता है। फिर भी, समझा जाता है कि बायजू ने बीसीसीआई को सूचित कर दिया है कि वह इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। कई हाई-प्रोफाइल अधिग्रहणों और नई फंडिंग की कमी के कारण कंपनी पिछले कुछ महीनों से वित्तीय संकट में है। वह उन कुछ कंपनियों से बाहर निकलना चाहती है जिनका उसने अधिग्रहण किया था। इसने लागत में कटौती के लिए अक्टूबर 2022 से 5,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

सेंसेक्स 200 अंक ऊपर चढ़कर खुला तो निफ्टी 20 हजार के करीब ओपन

नई दिल्ली । भारतीय शेयर बाजार में तेजी लगातार जारी है और सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर खुलने में कामयाब रहा है. निफ्टी फिर से बीस हजार के करीब है और इस लेवल को फिर से छू चुका है. कारोबार खुलने के थोड़ी देर बाद ही निफ्टी ने 20 हजार का अहम मनोवैज्ञानिक स्तर फिर से हासिल कर लिया और सेंसेक्स भी 66,500 के ऊपर चला गया है. विदेशी फंड्स की खरीदारी के चलते आज घरेलू शेयर बाजार को सपोर्ट मिल रहा है. शेयर बाजार की ओपनिंग में बीएसई का सेंसेक्स 207 अंक या 0.31 फीसदी की उछाल के साथ 66,381 पर खुला है. वहीं एनएसई का निफ्टी 86.85 अंक या 0.44 फीसदी की बढ़त के साथ 19,976 पर ओपन हुआ. इस तरह निफ्टी फिर 20,000 के लेवल के करीब खुला और बैंक निफ्टी भी 44 हजार के पार होकर खुला । कारोबार खुलने के एक घंटे के भीतर ही निफ्टी 116.10 अंक या 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 20,005 पर है. सेंसेक्स 387 पॉइंट या 0.59 फीसदी चढ़कर 66,561 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. यानी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने क्रमशः 20 हजार और 66,500 के महत्वपूर्ण लेवल को पार कर लिया है. सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में उछाल देखा जा रहा है और केवल 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरावट के लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं. नेस्ले और आईटीसी दोनों शेयर 0.15-0.15 फीसदी की गिरावट पर हैं. टॉप गेनर्स में विप्रो 2.10 फीसदी और टेक महिंद्रा 2.06 फीसदी ऊपर हैं. एमएंडएम का शेयर 2.04 फीसदी चढ़ा है और भारती एयरटेल 1.17 फीसदी की बढ़त पर है. एचसीएल टेक में 1.15 फीसदी की मजबूती देखी जा रही है. निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में बढ़त का रुख बना हुआ है और 7 शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं. चढ़ने वाले शेयरों में विप्रो 2.68 फीसदी तो हीरो मोटोकॉर्प 2.44 फीसदी ऊपर हैं. टेक महिंद्रा 2.20 फीसदी, एमएंडएम 2.13 फीसदी और एचसीएल टेक के शेयर 1.34 फीसदी की तेजी पर हैं. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई फायदे में रहा और साउथ कोरिया का कोस्पी, चीन का शंघाई और हॉन्गकॉग का हैंगसेंग नुकसान में दिखे हैं. अमेरिकी बाजार मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 81.66 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 783.82 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं.

सोने की चमक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, ऑलटाइम हाई पर पहुंचे गोल्ड रेट

नई दिल्ली ।

सुनहरी मेटल सोने की चमक ने नया रिकॉर्ड बना लिया है और एमसीएक्स पर सोने के दाम ऑलटाइम हाई पर आ गए हैं. सोना आज 62883 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ पहुंचा है जो इसका अभी तक का उच्चतम स्तर है. फ्यूचर मार्केट में कल सोना 62722 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ था. ध्यान रहे कि ये इसके फरवरी वायदा के रेट हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज खुलते ही गोल्ड ने 62800 रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल पार कर लिया और ये सोने का अब तक सर्वाधिक उच्च स्तर है. एमसीएक्स पर सोने का फरवरी वायदा सबसे ऊंचे स्तर 62833 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा और इसमें लगातार तेजी जारी है. इतनी ऊंचाई पर जाने के पीछे कारण हैं कि देश में शादियों के सीजन के चलते सोने की मांग काफी बढ़ी हुई है. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी गोल्ड रेट को लेकर पॉजिटिव खबरों का सिलसिला जारी है. कॉमैक्स पर गोल्ड 2044.30 डॉलर प्रति औंस पर है और इसमें 4.30 डॉलर या 0.21 फीसदी की बढ़त दर्ज की जा रही है. एमसीएक्स पर चांदी का दाम 164 रुपये या 0.21 फीसदी की बढ़त के साथ 77157 रुपये प्रति किलो के रेट पर आ गया है और इसमें भी बढ़त पर ट्रेडिंग हो रही है. चांदी के ये दाम इसके मार्च वायदा के लिए हैं. देश में शादी-विवाह के सीजन में सोना और चांदी दोनों कीमती मेटल्स जमकर खरीदी जाती हैं और 77 हजार का स्तर पार करके चांदी भी अपनी चमक और बिखेर रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का दिसंबर वायदा 62385 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और इसमें 2,347 लॉट का कारोबार देखा गया था. कल दिखी कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने डील साइज को घटाया जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखी गई थी लेकिन ये बढ़त के साथ ही बंद होने में कामयाब रहा.

महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का पहला दौर आज से शुरू

नई दिल्ली । सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का पहला दौर बुधवार को शुरू करेगी। इसमें 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों के 20 ब्लॉक देश भर में फैले हुए हैं। महत्वपूर्ण खनिज देश की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि नीलामी ऑनलाइन माध्यम से दो चरणों में की जाएगी। निविदा दस्तावेज की बिक्री बुधवार से शुरू होगी। बयान के अनुसार, ''खनिज ब्लॉक, नीलामी की शर्तों, समयसीमा आदि का विवरण एमएसटीसी नीलामी मंच पर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से आवश्यक खनिजों की उच्च मांग है। ऐसे खनिजों की मांग आमतौर पर आयात से पूरी की जाती है। महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा तथा कृषि जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये खनिज हमारी आर्थिक वृद्धि, देश और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। मंत्रालय ने कहा, ''यह एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का निर्माण करने में मदद करेगी। बयान में कहा गया, ''इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ देशों में ही इनकी बहुलता से आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) जैसे खनिजों पर निर्भर हैं। भारत 2030 तक बिजली की कुल स्थापित क्षमता में से हरित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव के महत्वकांक्षी लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रिक कार, पवन व सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा बैटरी भंडारण प्रणालियों की मांग बढ़ेगी। इससे इन महत्वपूर्ण खनिजों की मांग बढ़ जाएगी। हाल ही में खनन नियम में संशोधन के माध्यम से 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से आवश्यक खनिजों के रूप में अधिसूचित किया गया था। इन नीलामियों से उत्पन्न राजस्व राज्यों को मिलेगा।

शानदार एंट्री से आईआरईडीए ने दिया बंपर मुनाफा, 56फीसदी के प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग

नई दिल्ली। आईआरईडीए के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को शानदार मुनाफा मिला है। 32 रुपए के इश्यू प्राइस के सामने आईआरईडीए के शेयर 50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं और ये सीधा 56 फीसदी से ज्यादा के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग मिली है। एनएसई पर लिस्ट होते ही आईआरईडीए के शेयरों ने लिस्टिंग गेन मुहैया कराया है। आईआरईडीए के आईपीओ में शेयर प्राइस 32 रुपए था और लिस्टिंग 50 रुपए पर हुई है। सीधा अर्थ है कि हर एक शेयर पर निवेशकों को 18 रुपए की कमाई तुरंत मिल गई और ये इंवेस्टर्स को खुशी दे चुका है। एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर आईआरईडीए की लिस्टिंग 50 रुपए पर हुई है। इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स भी मिला था और ये ग्रे मार्केट में भी 37 फीसदी प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था। इससे संकेत मिल गए थे कि आईआरईडीए की शानदार लिस्टिंग होगी लेकिन स्टॉक 56 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट होंगे ये अंदाजा शायद नहीं था।

नहीं रहे वारेन बफे के भरोसेमंद सलाहकार चार्ली मंगर, 99 साल की आयु में ली आखिरी सांस

बिजनेस डेस्क ।

आज ग्लोबल वित्तीय जगह को एक बड़ा झटका लगा है। दिग्गज निवेशक और अरबपति वारेन बफे के सबसे भरोसेमंद साथी चार्ली मंगर नहीं रहे। उनका 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चार्ली मंगर के निधन की पुष्टि बर्कशायर हैथवे ने एक प्रेस रिलीज के जरिए की है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चार्ली मंगर की मृत्यु कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में हुई है। आने वाली 1 जनवरी को चार्ली अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले थे। चार्ली मंगर के निधन पर वारेन बफे ने दुख जताते हुए कहा कि बर्कशायर हैथवे की सफलता में चार्ली मंगर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वारेन बफे ने बर्कशायर हैथवे द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा कि चार्ली मंगर की भागीदारी और सलाह के बिना बर्कशायर हैथवे इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। कंपनी को बड़ा बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 1924 में अमेरिका में जन्मे मंगर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया था इसके बाद उन्होंने वित्तीय सेक्टर में एंट्री का मन बनाया। इसके बाद उन्होंने साल 1962 में वित्तीय लॉ फर्म Munger, Tolles & Olson की स्थापना की। बफे से मंगर की पहली मुलाकात साल 1959 में हुई थी। वित्तीय समझ ने दोनों को पार्टनर बना दिया। मंगर के पारिवारिक जीवन में उनकी छवि एक फैमिली मैन के रूप में थी। अपनी पत्नी Nancy Barry के साथ चार्ली मंगर 54 साल तक शादी के बंधन में बंधे रहे। साल 2010 में Nancy Barry की मृत्यु हुई थी। चार्ली मंगर की पहली शादी से तीन और दूसरी शादी से चार बच्चे हैं। नेट वर्थ की बात करें तो साल 2023 में चार्ली मंगर की नेट वर्थ 2.3 बिलियन डॉलर के आसपास रही है।

वह बर्कशायर हैथवे के वाइस प्रेसिडेंट पद के अलावा रियल एस्टेट के जाने माने वकील, कॉस्टको बोर्ड के सदस्य, डेली जर्नल कॉर्प के अध्यक्ष और एक बड़े परोपकारी के रूप में भी जाने जाते थे। वहीं दिग्गज निवेशक और कारोबारी वारेन बफे की नेट वर्थ 100 बिलियन डॉलर से अधिक है। साल 2021 में बर्कशायर हैथवे की सालाना बैठक के दौरान चार्ली मंगर ने कंपनी के भविष्य की प्लानिंग के बारे में बात करते हुए लीडरशिप में बदलाव के संकेत दिए थे।

उन्होंने बफे के बाद कंपनी के वाइस चेयरमैन ग्रेग एबेल को कंपनी की कमान सौंपने की वकालत की थी। वारेन बफे मंगर को हमेशा से अपना भरोसेमंद सलाहकार मानते थें और उन्होंने बफे के निवेश के तरीके में बहुत से बदलाव किए थे।

अलग-अलग प्रतियोगिताओं में बच्चे दिखाएंगे अपना हुनर

गोरखपुर।

मियां साहब इस्लामिया (एमएसआई) इंटर कॉलेज बक्शीपुर का वार्षिक जलसा-ए-सीरतुन्नबी एक, दो, तीन व चार दिसंबर को कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान दीनी तालीमी नुमाइश (धार्मिक शिक्षा प्रदर्शनी) भी लगाई जाएगी। जलसे में प्रदेश स्तर के विद्यालयों, मदरसों, स्थानीय प्राइमरी विद्यालय एवं मकतब के विद्यार्थियों के बीच किरात, नात, भाषण (तकरीर), पेंटिंग, वाद-विवाद, विज्ञान क्विज़, इस्लामी क्विज के मुकाबले होंगे। चार दिसंबर को विजयी विद्यार्थियों में इनाम वितरित किए जाएंगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य व जलसे के संयोजक जफर अहमद खां एवं सह संयोजक रिजवानुल हक ने बताया कि बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, वाराणसी, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे।

उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को शाम 6:00 बजे जलसा-ए-सीरतुन्नबी व दीनी तालीमी नुमाइश का उद्घाटन होगा।दो दिसंबर को मकतब व प्राइमरी ग्रुप (स्थानीय स्तर) और सान्वी व जूनियर ग्रुप का मुकाबला होगा। सुबह आठ व नौ बजे किरात (कुरआन पाठ) और इस्लामी क्विज का लिखित मुकाबला होगा। सुबह 10 व 11 बजे भाषण (तकरीर) प्रतियोगिता होगी।

दोपहर 2:00 व 2:30 बजे इस्लामी क्विज व शाम 5:30 बजे नातिया मुकाबला होगा। इसी क्रम में तीन दिसंबर को प्रदेश स्तर पर मदारिसे अरबिया ग्रुप का मुकाबला होगा।

सुबह आठ व नौ बजे किरात (कुरआन पाठ) का मुकाबला और दोपहर 1:30 बजे भाषण (तकरीर) प्रतियोगिता होगी। शाम 6:30 व आठ बजे नातिया मुकाबला होगा। इसी दिन स्कूल और कॉलेज ग्रुप के प्रदेश स्तर के मुकाबले होंगे।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध 870 दिनों से प्रचलित सत्याग्रह संकल्प पर लाचार व बीमार बनी सरकार

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट का यदि अवलोकन किया जाए तो प्रतिवर्ष अरबों खरबों रुपए के गंभीर वित्तीय अनिमियता व आर्थिक अपराध को अंजाम देते हुए अभियंताओं द्वारा सरकारी धनराशि का बंदरबांट किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के खण्डीय कार्यालयों में सीएजी आधारित लगभग करोडों रुपए के कारित भ्रष्टाचार के विरुद्ध तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा 870 दिनों से प्रचलित सत्याग्रह संकल्प से किया जा सकता है। परन्तु बड़े ही हैरत की बात है कि मुख्य मंत्री के गृह नगर में 870 दिनों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचलित सत्याग्रह संकल्प पर सरकार के समूचे तंत्र कार्रवाई करने में अब तक विफल है, अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री को आए दिन गोरखपुर आगमन पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचलित सत्याग्रह संकल्प नहीं दिखता? क्या सरकार के अन्वेषण विभाग द्वारा प्रेषित दैनिक रिपोर्ट के अनुरूप सत्याग्रह संकल्प संज्ञान में नहीं आता?क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध अहिंसात्मक सत्याग्रह संकल्प वैधानिक कार्यवाही के पात्र नहीं है? ये सभी अनुउत्तरित सवाल कहीं न कहीं इस बात का इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के प्रचलित व्यापार को सरकार और सरकार के करिंदों का संलिप्तता व संरक्षण है और शायद यही कारण है कि अभियंताओं द्वारा निरंकुश भ्रष्टाचार के व्यापार पर सरकार कार्रवाई करने में अक्षम है.

अनुपूरक बजट : 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा, महिला वोटरों को साधने की कोशिश

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात मिलेगी। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने की तैयारी की है। अनुपूरक बजट में निगम को प्रतिकर भुगतान के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में योगी सरकार का पूरा फोकस आधी आबादी के वोट बैंक को साधने पर है। प्रदेश में लंबे समय से बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की मांग की जा रही थी। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

रोडवेज के बेडे में शामिल होंगी एक हजार नई बसें

मंत्री सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बेडे में करीब एक हजार नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें सौ से अधिक इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी। अनुपूरक बजट में नई बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हाल ही में कैबिनेट से स्वीकृत उत्तर प्रधेश अंतर्देशीय

जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान किया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय में वाहन खरीद के लिए 50 लाख का बजट प्रावधान किया है।

रोडवेज दफ्तरों के लिए मंजूरी

अनुपूरक बजट में बरेली, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड़, देवरिया, संभल, जौनपुर, चित्रकूट और चंदौली में सारथी हॉल सहित रोडवेज कार्यालय भवन बनाने के लिए अनुपूरक बजट में मंजूरी दी गई है। अनुपूरक बजट में टोकन मनी के रूप में एक लाख रुपये स्वीकृत किया है।

हजरतगंज में बनेगा एकीकृत परिवहन भवन

राजधानी लखनऊ में हजरत गंज ओलिवर रोड पर स्थित भूमि पर परिवहन विभाग का बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन भवन बनाया जाएगा। अनुपूरक बजट में भवन निर्माण को मंजूरी के साथ इसके लिए टोकन मनी के रूप में एक लाख रुपये का प्रावधान किया है।

तेज रफ्तार कार से बाइक सवार सहित 3 की हुई मौत

सिरकोनी, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र के जफराबाद स्थानीय कस्बे के ताड़तला मुहल्ले में बुधवार की सुबह तेज रफ्तार अनियन्त्रित कार ने बाइक सवार युवक सहित 4 लोगों को रौंद दिया।घटना में 3 लोगों की मौत हो गयी तथा एक युवक गम्भीर रूप से घायल हो गया। वह जिला चिकित्सालय में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। जानकारी के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के समैसा गांव निवासी ओमकार यादव के लड़की जया की मंगलवार को शादी थी। बुधवार को सुबह बारात विदा हो गयी। कोई जरूरी सामान छुट गया था। ओमकार का पुत्र देव आशीष यादव अपने एक साथी साथ सिरकोनी धौरहरा से वह सामान देकर लौट रहा था।लोगों ने बताया कि उक्त स्थान पर कार की रफ्तार अत्याधिक तेज थी। कार ने उक्त स्थान पर स्थित एक गोमटी मे कुछ लोग चाय पी रहे थे। कार ने वहां मौजूद 3 लोग तथा एक बाइक से जा रहे युवक को रौंद दिया। कार के चपेट में आये सेवालाल 70 वर्ष निवासी ऊँचवापर थाना जलालपुर, राजदेव यादव 62 वर्ष निवासी बीघही थाना जलालपुर तथा शहनवाज 26 वर्ष पुत्र आफताब निवासी नैपुरा की मौत हो गई। जवाहिर पाल 23 वर्ष पुत्र बाबा पाल निवासी नैपुरा को अत्याधिक गम्भीर चोट आई है। वह भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। घटना के बाद लोगों ने कार चला रहे देवा आशीष यादव तथा कार में सवार एक अन्य युवक को पीटना शुरू कर दिया। उसी समय कुछ लोगों ने दोनों को एक घर मे घुसा कर बचा लिया।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी किशोर कुमार चौबे मय फोर्स मौके पर पहुंच गये। उन्होंने सभी को जिला चिकित्सालय भिजवाया। मामला काफी उग्र होने लगा। तब तक सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गये। उन्होंने घटना स्थल की स्थिति को डेढ़ घण्टे तक सामान्य किया। उसके बाद कार चालक व उसके साथी को निकाल कर अपने कस्टडी में लेकर थाने भिजवाया। ज्ञात हो कि चैयरमैन के पति डॉ सरफराज खान व विकास यादव नामक युवक के कारण दोनों की जान बच गयी।

यूपी विधानसभा : जातिवार जनगणना के मुद्दे पर सपा सदस्यों ने किया सदन से बहिर्गमन

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जातिवार जनगणना को लेकर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सपा सदस्यों ने प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर शून्य काल के दौरान कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। नोटिस में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समय-समय पर जातिवार जनगणना करने की बात कहती आ रही है लेकिन 2021 में नियमित जनगणना होने जा रही थी तो भाजपा ने जातिवार जनगणना कराए जाने से किनारा कर लिया। उसमें कहा गया है, ÷खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के वक्त जातिवार जनगणना की बात कही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। समाजवादियों की मांग पर वर्ष 2011 में जातिवार जनगणना कराई गई थी मगर सरकार ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। नोटिस में कहा गया है, ÷सभी वर्गों को अपनी आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिले इसके लिए जातिवार जनगणना ही एकमात्र रास्ता है, लिहाजा इस पर सदन का बाकी काम रोक कर चर्चा कराई जाए।÷ सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने नोटिस को स्वीकार करने पर बल देते हुए कहा, न जाने किन कारणों से भाजपा सरकार जनगणना करने से भाग रही है। वर्ष 2021 से जातिवार जनगणना तो छोड़िए सामान्य जनगणना भी नहीं हो रही है। जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। उन्होंने दावा किया, लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 30 प्रोफेसर और 132 सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद वहां

आरक्षण को बिल्कुल निष्प्रयोय कर दिया गया। पटेल ने आरोप लगाया, ÷प्रदेश में जाति के नाम पर अन्याय हो रहा है। प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सपा सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नोटिस को स्वीकार करने पर बल देते हुए कहा कि वर्ष 2010 में भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा था कि अगर 2011 में जातिवार जनगणना करके पिछड़ों के हित का ख्याल नहीं किया गया तो इस वर्ग के लोग 10 साल पीछे हो जाएंगे। उन्होंने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहा था कि जब हम आगे सरकार में आएंगे तो जातिवार जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा, लगभग 100 ऐसी जातियां हैं जिन्हें बाद में पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया है। बाद में पिछड़े वर्ग में शामिल की गई जातियों को आनुपातिक रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेता सदन एवं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जब शासन में रहती है तब उसे पिछड़ों और गरीबों की याद नहीं आती है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, किसी भी भर्ती को लेकर आरक्षण का मामला हो, उस पर सरकार पारदर्शी है। मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आरक्षण के मामले में एक भी बच्चों के साथ हमने अन्याय नहीं होने देंगे। अगर अदालत में कोई मामला है तो हम न्यायालय की अवमानना करके उसपर कोई निर्णय नहीं ले सकते। जहां भी अन्याय हुआ है उसे रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारा काम है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा सदस्यों ने जातिवार जनगणना का विषय रखा है। वे सभी वरिष्ठ लोग हैं और जानते हैं कि यह जनगणना केंद्र सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने कहा है कि वे जातिवार जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सपा जातिवार जनगणना करने की बात तो करती है लेकिन वह ऐसा करने के पक्ष में नहीं है लिहाजा सपा सदस्यों का नोटिस खारिज करने योग्य है। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कार्य स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर उसे सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए। नरेश उत्तम पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, लाल बिहारी यादव समेत सपा सदस्यों ने नेता सदन के उत्तर पर असंतोष जाहिर किया और नेता सदन से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में हुई भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा और सभापति द्वारा रोके जाने के बाद सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इसके पूर्व, नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक अनुदान मांगों को पेश किया।

उपायुक्त, रोहिणी जोन, दि.न.नि के संरक्षण में

नांगलोई, किराड़ी व सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्डो में गली, नाली/नाला, सड़क, पुलिया, पार्क, फुटपाथ के विकास एवं निर्माण कार्यो में करोड़ो का घोटाला व भ्रष्टाचार की श्रीमान निदेशक, सी.बी.आई, भारत सरकार से जांच की मांग।

सहायक व कनिष्ठ अभियंता बने "अडानी"

एम-1, वर्क्स विभाग, रोहिणी जोन के ई.ई, ए.ई-1,2,3 श्री महिपाल सिंह, संजीव कुमार, जी.एस.ब्रिजवाल, जे.ई की मिलीभगत से किए करोड़ो के घोटाले ही घोटाले.....

वार्ड-37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 में किये जा रहे व किये गए विकास एवं निर्माण में लगाई बेहद घटिया निर्माण सामग्री, एमसीडी को लगाया अभियंताओं ने करोड़ो का चूना।

C-2 Shop No.1 DDA market to C-BLOCK school, Sultanpuri

Women's Park No 64 in front of Peerbaba Mazar, Sultanpuri

भैंरा एन्कलेव, पश्चिम विहार

अघर ए.ई बी संजीव के द्वारा भ्रष्टाचार की काली कमाई से खरीदी गई 25 लाख रूपये किमत वाली वाईट रंग की क्रेटा कार और उसपर 40 हजार रूपये महिने का ड्राईवर आखिर कहां से आ रही है इतनी मोटी काली कमाई और किनका है इनके ऊपर आर्शिवाद कृपाएं श्रीमान निदेशक, सी.बी.आई, भारत सरकार से मांगा

अभियंताओं ने बनाई करोड़ो रूपये की बेनामी सम्पत्ति खरीदी अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम महंगी-महंगी लग्जरी कारें उसपर 40-40 हजार के ड्राईवर से चलते है, स्वयं व इनके परिवार

एप्पल का मोबाईल व लेपटॉप और पी.पी.डिजाईनर के कपड़े, रोलेक्स की घड़ी, बूची के जूते, लग्जरी कारो स्वंय व परिवार के लिए प्राईवेट ड्राइवर 40-40 हजार प्रतिमाह, शाम का डिनर बड़े रेस्टुरेंट, होटल और क्लबों और लाखों की ज्वैलरी और अडानी की तरह आलीशान जिन्दगी जी रहे है।

अध्यक्षः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....